Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding the privatisation of BPCL.

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटैड से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । माननीय वित्त राज्य मंत्री जी ने 18 तारीख को इसी सदन में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि केंद्र सरकार इसी वित्त वर्ष में 28 सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है जिसमें एयर इंडिया सहित बीपीसीएल के निजीकरण के लिए सरकार की एक योजना है । मेरी जानकारी के अनुसार सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह को पहले ही बीपीसीएल के निजीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है । बीपीसीएल की चैंबूर रिफाइनरी, मुंबई के प्रबंधन और कर्मचारियों ने मुझसे संपर्क किया और सरकार के अनुचित प्रस्ताव के बारे में अपनी पीड़ा बताई । यह भी रिर्पोट में है कि कानूनी सलाहकार की नियुक्ति के लिए निजीकरण और विज्ञापन की प्रक्रिया पहले ही समाचार पत्रों में जारी की जा चुकी है । बीपीसीएल को पिछले कई वर्षों के अपने निरंतर प्रदर्शन के लिए वर्ष 2017 में महारत्न का दर्जा दिया गया था । यह पिछले 16 वर्षों से ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से एक है । तब हम, बीपीसीएल के निजीकरण के प्रस्ताव के कारणों को समझने में असमर्थ हैं । पेट्रोलियम क्षेत्र देश के विकास के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है और बीपीसीएल ने अपने राष्ट्रीयकरण के बाद वर्ष 1976 से अपना योगदान साबित किया है । मेरे विचार में, बीपीसीएल का निजीकरण हमारे राष्ट्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है ।

महोदय, मैं कनक्लूड कर रहा हूं । जिसके परिणामस्वरूप तेल क्षेत्र में निजी एकाधिकार हो सकता है, जो ऊर्जा सुरक्षा को देखते हुए हमारे राष्ट्र के लिए

खतरनाक होगा । अधिकारियों और कर्मचारियों का भविष्य दांव पर है ।

निजीकरण से प्रभावित होने वाले हितधारकों की लंबी सूची है, जैसे कंपनी के कामगार और अधिकारी, दिहाड़ी मज़दूर, ठेकेदार, सीएसआर गतिविधियां, मछुआरों को डीजल सब्सिडी, ठेकेदारों के श्रम, विक्रेता, सुरक्षा, आदि । यह न केवल चेंबूर रिफाइनरी में है, बल्कि पूरे देश में बड़ी संख्या में हैं । इसलिए, मैं मांग करता हूं कि सरकार को ऐसे कठोर प्रस्तावों को रोकना चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा और लोगों के हित में बीपीसीएल सहित किसी भी पीएसयू के निजीकरण के विचार पर एक बार फिर सोचना चाहिए । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री सप्तगिरी उलाका एवं श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को श्री राहुल रमेश शेवाले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है । माननीय सदस्यगण, अगर सदन की सहमति हो तो कई माननीय सदस्य शून्य काल में बाकी हैं, सात बजे तक का समय बढ़ा दिया जाए ?

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ महोदय ।